Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 24-08-2006

Participants : Mohale Shri Punnulal

an>

Title : Need to sanction funds under vaious developmental schemes for the welfare of SCs and STs.

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, जनजातीय कार्यालय आदिम जाति अनुसूचित विकास विभाग तथा जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए प्रति वर्ा जो राशि दी जाती है, वह नहीं दी जा रही है। इस कारण वर्ा 2004 से अनेक योजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें स्वीकृत नहीं करने से उक्त वर्गों में आक्रोश भरा हुआ है तथा सरकार के प्रति वे लोग उदासीन हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए राशि न मिलने से विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इलाकों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक संस्था के लिए 1,31,564 रुपए नहीं मिल रहे हैं। विशेा पिछड़ी जनजाति को सुविधा युक्त आवास देने के लिए 100 परसेंट अनुदान स्कीम के लिए 7,28,870 रुपए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हेतु 162 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ जिला काकेर में आदिवासी संग्राहलय की स्थापना के लिए 6,54,281 रुपए, कोचीन एवं अलाइड के लिए 1,531 लाख रुपए एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय की वित्त योजना के लिए 3,282 लाख रुपए की योजनाएं हैं। वर्ा 2004 से ये योजनाएं लम्बित हैं तथा केंद्र सरकार के पास उपरोक्त

- The speech was laid on the Table.

ह्मंत्रालयों में विचाराधीन हैं और इन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है। उक्त योजनाओं को केंद्र सरकार अविलम्ब स्वीकृति दे। सामाजिक, शैक्षणिक, आवास, संग्राहलय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आईएएस, आईपीएस और टेक्नालोजी के प्रशिक्षण तथा अन्य विभिन्न योजनाओं जैसे पानी की सुविधा, सभी प्रकार के नशे को ख्यागने की योजना, कन्या विवाह हेतु अनुदान एवं उक्त वर्गों के विकास के कार्यों के लैलए लगभग सरकार 2 हजार करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत करे।